हिंदी दैनिक
न्यूज़ वायरस
वर्ष : 11 अंक : 159 देहरादून, मंगलवार, 13 दिसंबर, 2022 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण और मौसम विज्ञान केन्द्र का एमओयू बढ़ा
3

625.62 लाख की सौगात देकर सतपाल महाराज ने विकास को दी नई उड़ान

वर्क कल्चर डेवलप करते हुए विकास कार्यों में सहयोग करें अफसर : महाराज

देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रुद्रप्रयाग, 12 दिसंबर। पंचायतें मजबूत होकर अपनी आर्थिकी के साधन तैयार करें। अधिकारी छोटी-छोटी समस्याओं का निस्तारण निचले स्तर पर ही शीघ्रता से करें। जनपद मुख्यालय पर लोक निर्माण एवं पंचायती राज विभाग की 625.62 लाख की धनराशि की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने अपने संबोधन में कही। शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम से पहले कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने तिलवाड़ा स्थित पर्यटक आवास गृह में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात कैबिनेट मंत्री महाराज द्वारा जिला कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी राज्य एवं जनपद के विकास के लिए वर्क कल्चर डेवलप करते हुए विकास कार्यों में अपनी संपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजाओं का लाभ आम जनमानस तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जनता एवं जन प्रतिनिधियों

द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जाती हैं उनका यथाशीघ्र सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समाधान करें।उन्होंने कहा कि जनपद में बाबा केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं तथा केदारनाथ यात्रा को और अधिक सुगम और सरल बनाने के लिए इस दिशा में सभी को बेहतर ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले तीर्थ यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि यह जनपद पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए पर्यटन सर्किट बनाए जाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है। प्राचीन मंदिरों को और अधिक विकसित करते हुए उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। कार्तिक स्वामी एवं कालीमठ को भी डेवलप किया जाएगा। महाराज ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद के अंतर्गत जो भी सड़के हैं उन सभी सड़कों को सुगम यातायात के लिए दुरस्त कर गड्ढा मुक्त किया जाए। उन्होंने बेलनी पुल में आवश्यक सेवा एंबुलेंस की आवाजाही के लिए निर्देश देते हुए बेलनी पुल के निर्माण एवं मरम्मत संबंधी जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा से जो भी योजनाएं क्षतिग्रस्त होती हैं उन योजनाओं का प्रस्ताव तत्परता से प्रस्तुत करते हुए प्राथमिकता से कार्य शुरू किया जाए। उन्होने कहा कि सड़कों की नालियों की रख-रखाव व मरम्मत के लिए इस दिशा में स्थानीय लोगों एवं महिला मंगल दलों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने पंचायतों को और अधिक मजबूत करने तथा पंचायतों की आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए सभी को इस दिशा में बेहतर ढंग से कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा।

इन योजनाओं का हुआ लोकार्पण व शिलान्यास

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखंड अगस्त्यमुनि में डूंगरा (बच्छणस्यूं) से आरस्यूं के मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य, लागत 97.51 लाख, का शिलान्यास, केदारनाथ विधानसभा में बांसवाड़ा से किरोदी-जलई-गैर-कंडारा मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य लागत 147.00 लाख का लोकार्पण, राज्य योजना (नाबार्ड-24) के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग के विकासखंड अगस्त्यमुनि में कोटेश्वर में अलकनंदा नदी पर 46 मीटर स्पान स्टील गार्डर लोह सेतु के निर्माण कार्य, लागत 85.93 लाख का लोकार्पण, विकासखंड जखोली में धान्यू कोटी घरड़ा मोटर मार्ग के डामरीकरण का लोकार्पण, लागत 156.12 लाख और जिला योजना के अंतर्गत केदारनाथ विधानसभा में भटवाड़ी-सुनार- चंद्रापुरी मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य, लागत 33.60 लाख का शिलान्यास।इसके अलावा पंचायतीराज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत जनपद के विकासखंड जखोली की ग्राम पंचायत थातीबड़मा में प्रस्तावित पंचायत भवन के निर्माण कार्य लागत 10 लाख, ग्राम पंचायत धनकुराली में प्रस्तावित पंचायत भवन के निर्माण कार्यों, लागत 10 लाख, ग्राम पंचायत खोड में प्रस्तावित पंचायत भवन के निर्माण कार्य, लागत 10 लाख का शिलान्यास। विकासखंड जखोली ग्राम पंचायत डांगी भारदार में पंचायत भवन के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य, लागत 5 लाख, ग्राम पंचायत बश्ता बदमा में पंचायत भवन के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य लागत 5 लाख और मलयाली में 5 लाख 23 हजार की लागत के कंपैक्टर का शिलान्यास किया। विकासखंड उखीमठ के अंतर्गत ग्राम पंचायत भेंसारी में प्रस्तावित पंचायत भवनों के निर्माण कार्य, लागत 10 लाख, ग्राम पंचायत कुण्डजेठी में प्रस्तावित पंचायत भवनों के निर्माण कार्यों लागत 10 लाख, ग्राम पंचायत ल्वारा में प्रस्तावित पंचायत भवन के निर्माण कार्य, 10 लाख, ग्राम पंचायत ल्वारा में पंचायत भवन में अतिरिक्त कक्ष निर्माण लागत 5 लाख, गुप्तकाशी में पंचायत भवनों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य, लागत 5 लाख, मनसूना में पंचायत भवनों के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य लागत 5 लाख और कालीमठ में 5 लाख 23 हजार की लागत के कंपैक्टर का शिलान्यास किया।विकासखंड अगस्त्यमुनि में ग्राम पंचायत भवन के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य, लागत 5 लाख और ग्राम पंचायत वीना में 5 लाख की लागत से बनने वाले पंचायत भवन के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

राज्य कर के लकी ड्रॉ की वित्तमंत्री प्रेमचंद और कमिश्नर डॉ. अहमद इकबाल ने की घोषणा

मो.सलीम सैफी
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 12 दिसंबर। वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने राज्य कर मुख्यालय, में राज्य कर द्वारा उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना 'बिल लाओ ईनाम पाओ' के अंतर्गत प्रथम मासिक लकी ड्रॉ की घोषणा की गई। इस दौरान 1500 ग्राहकों को मासिक लकी ड्रॉ के लिए रैंडमली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चुना गया। जिसमे प्रथम 500 लोगों को इनाम के रूप में मोबाइल फोन, द्वितीय स्थान पर 500 लोगों को स्मार्ट वॉच एवं तृतीय स्थान पर 500 लोगों को ईयरफोन दिए जाने घोषणा की गई।

वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने "बिल लाओ ईनाम पाओ" योजना लागू की है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करना है। उन्होने कहा इस तरह हर प्रकार की खरीद पर बिल प्राप्त करने की जागरूकता के माध्यम से राजकोष को सुरक्षित करने में समस्त हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2023 तक प्रत्येक माह उपभोक्ताओं के पास बिल अपलोड करने पर मासिक पुरस्कार जीतने का अवसर होगा। लकी ड्रा की घोषणा के उपरान्त लकी ड्रा विजेताओं को सूचित किया जाएगा तथा विभाग की चयनित टीम द्वारा उनके सत्यापन के उपरान्त ही पुरस्कार दिये जायेंगे। लकी ड्रा की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री द्वारा समस्त जनता से खरीद पर बिल प्राप्त करते हुए राज्य के विकास तथा खुशहाली में योगदान देने की अपील की गयी। आयुक्त राज्यकर डॉ. अहमद इकबाल ने कहा सभी ग्राहक अपने बिल blipuk app पर अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा इस माह कुल 6058 जीएसटी बिल एप के माध्यम से प्राप्त हुए हैं।

आज के पहले लकी ड्रा में 01 सितम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2022 तक की अवधि में की गयी खरीद पर अपलोड किये गए बिलों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना की अवधि की समाप्ति पर माह अप्रैल या मई, 2023 में मेगा लकी ड्रा का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें ग्राहकों को कारें, इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, लैपटॉप, माइक्रोवेव जैसे 10 करोड़ के विभिन्न पुरस्कार जीतने का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर अपर आयुक्त अमित गुप्ता, अनिल सिंह, ईश्वर सिंह बृजवाल,अनुराग मिश्रा, प्रीति मनराल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

ऊर्जावान नेतृत्व में गुजरात विकास के पथ पर गतिशील रहेगा : धामी

गुजरात, 12 दिसंबर। गुजरात की नई सरकार के शपथ ग्रहण में उत्तराखंड के सीएम धामी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाँधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में भूपेन्द्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के ऊर्जावान नेतृत्व में गुजरात विकास के पथ पर गतिशील रहेगा। इस दौरान सीएम धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाक़ात की।

भारतीय महिलाएं प्यार में नहीं गुस्से में हैं दुनिया में अव्वल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 12 दिसंबर , ये खबर आपको थोड़ा हैरान करेगी क्योंकि भारतीय लड़कियां , महिलायें अपनी भावनाओं , ममता और प्रेम के लिए जानी जाती हैं। लेकिन पिछले एक दशक में लोगों के बदलते मानसिक हालात जानने और उनकी भावनाएं समझने के लिए जब गैलप वर्ल्ड पोल ने 2012 से 2021 तक 150 देशों के 12 लाख लोगों पर सर्वे किया तो सच्चाई कुछ और सामने आई है। इसमें उन्होंने बताया कि 10 साल पहले महिला-पुरुष में गुस्सा और तनाव का स्तर समान था, लेकिन 10 साल से महिलाओं में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। वे अब ज्यादा आक्रोशित होने लगी हैं। हैरानी कि बात है कि भारत जैसे नारी सम्मान में सबसे आगे रहने वाले देश में औरते सबसे ज्यादा गुस्सैल बताई गयी हैं।

महिलाओं में गुस्से का स्तर 6% ज्यादा

आंकड़ों में कहें तो दुनियाभर में महिलाओं में आक्रोश का स्तर पुरुषों से 6% ज्यादा है। भारत और पाकिस्तान की महिलाओं में तनाव और गुस्से का स्तर दुनिया से दोगुना, यानी 12% है। भारत में जहां पुरुषों में गुस्से का स्तर 27.8% है, वहीं महिलाओं में यह 40.6% है। कोरोना महामारी के दो सालों में यह और भी ज्यादा बढ़ा।

महिलाओं में बढ़ते तनाव और गुस्से की

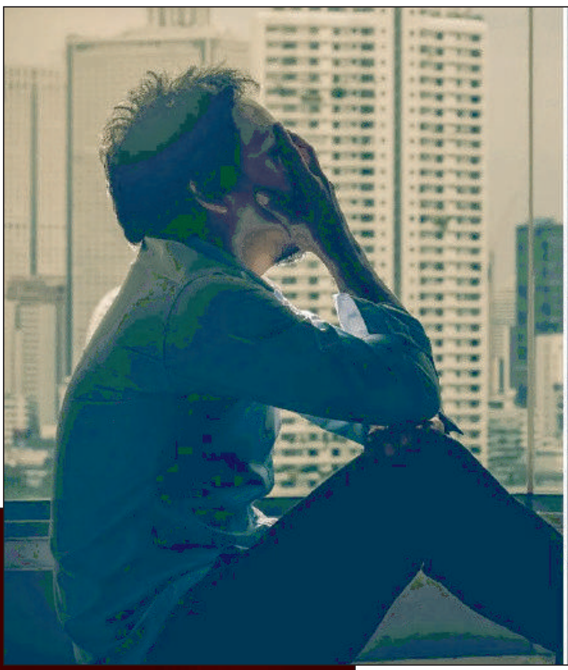

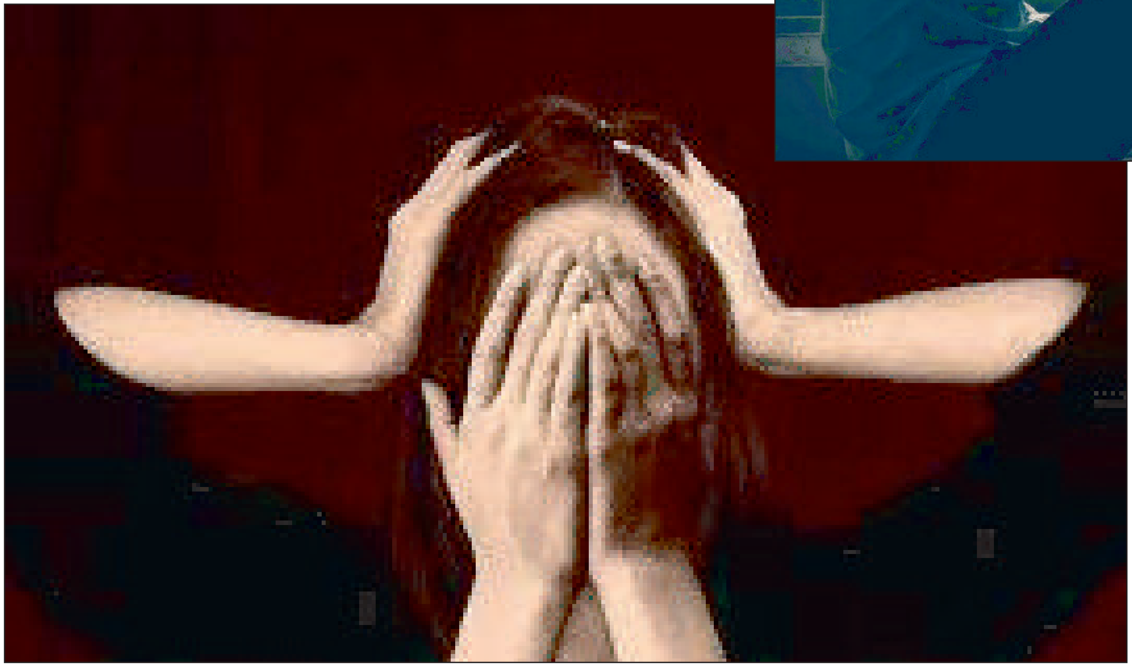

वजह बताती हैं। वे कहती हैं- तमाम देशों में महिलाएं पहले से ज्यादा शिक्षित हुईं और नौकरी करने लगीं। इससे उनमें आत्मनिर्भरता को लेकर कॉन्फिडेंस आया, लेकिन घरों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था अभी बरकरार है, जबकि बाहर बराबरी की बात की जाती है।

इस असंतुलन के बीच पिस रही महिलाएं अब आवाज उठाने लगी हैं। वे अपना गुस्सा जाहिर करने लगी हैं। पहले महिलाओं का गुस्सा करना गुस्से की वजह से भी ज्यादा बुरा माना जाता था। हालांकि समाज की सोच बदली है। अब यह नैतिक दबाव कम हुआ है। एक दशक में महिलाएं अपनी भावनाएं जाहिर करने में मुखर हुई हैं।

कम वेतन, ज्यादा अपेक्षाओं से गुस्सा बढ़ रहा

महिलाओं के गुस्से पर किताब 'रेज बिकम्स हर' लिखने वाली लेखिका सोराया शेमली कहती हैं- स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, लेकिन काम की अपेक्षा वेतन कम मिलता है। उनसे अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, यही अपेक्षा महिलाओं से घरों में भी होती है। इस वजह से उनमें गुस्सा बढ़ रहा है। भारत में महिलाएं पहले से ज्यादा प्रोफेशनल हो रही हैं। नौकरी और घर परिवार की दोहरी जिंदगी ने उन्हें बेहद तनाव में ला दिया है। ऐसे में चिड़चिड़ापन और गुस्सा स्वाभिक रूप से बढ़ा है।

जानिए मरने के बाद 13 दिन तक अपने घर में क्यों रहती है.... आत्मा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ज़ैसे जीवन एक सत्य है वैसे ही सभी भली भांति जानते हैं कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे जितना चाहो झुठलाया जा सकता है पर बदला नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ते हैं। हम में से कई लोगों ने अपने बड़ों को इस बारे में कई बार कहते सुना होगा कि मरने के बाद इंसान की आत्मा 13 दिन तक अपने घर में रहती है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी बताते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों 13 दिनों तक मृत शरीर की आत्मा अपने घर में भटकती रहती है साथ ही हम बताएंगे कि आखिर क्यों किया जाता है पिंडदान 13 दिन।

बता दें कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस जीव की आत्मा को वापस घर छोड़ देते हैं। यमदूत द्वारा आत्मा को वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने रिश्तेदारों के बीच भटकती है और अपने रिश्तेदारों को पुकारती है लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर-जोर से रोने लगती है।

इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है लेकिन यमदूत के प्रतिबंध के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण की मानें तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है, मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, और ग्यारहवें और बारहवें दिन जो शरीर किया जाता है, उसके मांस और त्वचा का निर्माण होता है। आत्मा बनती है। और जब 13वें दिन 13वां हो तो उस दिन मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है। वहीं से ही यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। यानी मृत्यु के बाद मृतक के नाम पर पिंडदान किया जाता है। उसी से आत्मा को मृत लोक से यमलोक की यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने रिश्तेदारों के पास घर में भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक को यमलोक की ओर छोड़ देती है, जिसे पूरा करने में उसे 12 महीने यानी 1 वर्ष का समय लगता है। इतना ही नहीं मान्यता के अनुसार 13 दिन तक मृतक के नाम से किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के बराबर फल देता है इसके अलावा आपको बता दें कि अक्सर लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम पर पिंडदान नहीं किया जाता है तो क्या होता है तो बता दें कि इसके बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में। जिस मृत व्यक्ति का पिंडदान नहीं हुआ है।

13वें दिन यमदूत जबरदस्ती उसे यमलोक की ओर खींच ले जाते हैं और इस दौरान मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13वें दिन परिवार के सदस्य मृत व्यक्ति के नाम पर भोज का आयोजन करते हैं। अगर कर्ज लेकर किया जाता है तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इतना ही नहीं गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीते जी अच्छे कर्म करता है.. यमदूत मृत्यु के बाद की यात्रा के दौरान और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा को कोई कष्ट नहीं देते हैं। यात्रा के दौरान यमदूत अपनी आत्मा को अनेक यातनाएं देते हैं और आत्मा को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण और मौसम विज्ञान केन्द्र का एमओयू बढ़ा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 दिसंबर, राज्य में वर्षा तथा मौसम संबंधी आपदाओं के जोखिमों से बचाव तथा आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए वेदर नेटवर्क स्टेशनों की स्थापना तथा वास्तविक समय मौसम सूचना प्रणाली (रियल टाइम वेदर इन्फॉर्मर सिस्टम) के विकास हेतु पूर्व में किए गए एमओयू (समझौता ज्ञापन) को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) तथा मौसम विज्ञान केन्द्र (आईएमडी) के मध्य सचिवालय में आगामी पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। सचिव आपदा प्रबन्धन डा0 रंजीत कुमार सिन्हा तथा मौसम विज्ञान केन्द्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। केन्द्रीय एजेंसी आईएमडी तथा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के मध्य यह एमओयू राज्य में आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद किए जाने वाले सहयोग, समन्वय और सहायता की दिशा में पहल है।

एमओयू के तहत आईएमडी द्वारा चयनित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज, ऑटोमेटेड स्नो गेज तथा कॉम्पेक्ट डॉप्लर राडार के स्थल चयन, इंस्टॉलेशन, परीक्षण तथा संचालन हेतु मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाए जाएंगे। यूएसडीएमए की सहायता से स्थापित इस पूरे तंत्र के अंतिम निरीक्षण में आईएमडी सहायता करेगी। उक्त उपकरणों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी यूएसडीएमए की होगी। इन उपकरणों से प्राप्त डाटा को प्रोसेसिंग के लिए सीधे आईएमडी के सर्वर में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही यूएसडीएमए को उत्तराखण्ड में आईएमडी द्वारा स्थापित अन्य मौसम सम्बन्धित उपकरणों तक रियल टाइम ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा। एमओयू के तहत आईएमडी तथा यूएसडीएमए शोध तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग एवं सहायता को प्रोत्साहित करेंगे। इसके तहत सूचनाओं तथा अनुभवों को भी आदान-प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबन्धन डा0 रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा उत्तराखण्ड एक आपदा संवेदशील राज्य है। यहां पर मुख्यतः वर्षा सम्बन्धित आपदाओं भूस्खलन, बाढ़, बिजली गिरने जैसे जोखिमों की अधिकता है। आईएमडी (मौसम विज्ञान केन्द्र) केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला है। पिछले कुछ वर्षों में आईएमडी का नेटवर्क उत्तराखण्ड में सघन किया गया है। केन्द्र सरकार के मौसम विज्ञान केन्द्र तथा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मध्य यह एमओयू एक नई पहल है। यह प्रधानमंत्री के विचारो के अनुरूप कॉपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। इसमें एक केन्द्रीय एंजेसी राज्य के साथ राज्य की जरूरतों के अनुसार आपदा प्रबन्धन हेतु प्रभावी व्यवस्था बनाने हेतु भागीदारी कर रही है। हाल ही में मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रगतिशील कार्य हुए है। सेटेलाइट सिस्टम एवं राडार सिस्टम में और भी अधिक प्रगति हुई है।

अब आईएमडी का पूर्वानुमान लगभग सटीक होता है। लेकिन इसमे और अधिक सटीकता की आवश्यकता है। हम इसे एक चरण आगे लेकर जाना चाहते हैं। हमें अब लोकेशन स्पेसफिक सूचना की आवश्यकता है। ताकि जहाँ पर कोई आपदा होने की आंशका है वहाँ पर आपदा प्रबन्धन का तंत्र पहले ही सतर्क एवं तैयार हो जाए। राज्य में दो राडार सिस्टम सुरकंडा देवी तथा मुक्तेश्वर में स्थापित हो चुके हैं तथा एक अन्य राडार सिस्टम लैंसडाउन में स्थापित किया जा रहा है। राज्य में राडार सिस्टम को सघन करने से लोकेशन स्पेसफिक सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी। लाइटनिंग राडार तथा ऑटोमेटेड डॉप्लिंग राडार को मिलाकर भी लोकेशन स्पेस्फिक सूचनाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस अवसर पर अपर सचिव सविन बंसल भी उपस्थित थे।

धामी सरकार से मदरसा टीचरों की अपील

न्यूज़ वायरस एक्सक्लूसिव

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 12 दिसंबर, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन जनाब ये खबर सच है। काम सबसे पवित्र और महान, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल ... जीरो मेहनताना और लगन सौ फीसदी .... जी हाँ आज बात उस समस्या की करेंगे जो सरकार, विभाग और सिस्टम के लिए रूटीन की है लेकिन इस मुसीबत को झेल रहा है तीन सौ से ज्यादा परिवार, क्या है मामला आपको बताते हैं।

उत्तराखंड को एजुकेशन हब माना जाता है। यहाँ के शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए देश के तमाम राज्यों से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन सरकार की मदद और आर्थिक सहयोग से चलने वाले मुस्लिम मदरसों की हालत कहीं से भी दुरुस्त नहीं कही जा सकती है। मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड और राज्य व केंद्र सरकार से मिलने वाली तनख्वाह के लिए एसपीक्यूएम योजना से 180 मदरसों के 494 मास्टर अपनी चार साल 2016 से 2020 तक की रुकी 36 करोड़ 23 लाख की सेलरी की वजह से गुरबत झेलने को मजबूर हैं। एक तरफ मदरसों को स्मार्ट बनाने, डिजिटल क्लास और ड्रेस, सेलेबस के दावे किये जा रहे हैं दूसरी तरफ इन्ही मदरसों के नाउम्मीद हो रहे गुरूजी तनख्वाह का बस इंतज़ार ही कर रहे हैं लेकिन सिस्टम की बलिहारी फाइलें आज तक मेज़ दर मेज़ हिचकोले ही खा रही है।

न्यूज़ वायरस से ख़ास बातचीत में बोर्ड के डिप्टी रजिस्टर यामीन अंसारी बताते हैं कि एसपीक्यूएम योजना में मदरसा टीचरों को 10 फीसद राज्य सरकार और 90 फीसदी केंद्र सरकार मिलकर तनख्वाह देती है लेकिन बीते चार साल से इन टीचरों को न तनख्वाह मिल पाई है और न ही उम्मीद ... बोर्ड रजिस्टर हांलाकि ये जरूर बताते हैं कि मौजूदा वित्तीय साल में इन 494 टीचरों का बीते 6 महीने की तनख्वाह 3 करोड़ 55 लाख जरूर जारी हो या है। लेकिन लाख भागदौड़, मीटिंग और अनुरोध के बाद भी चार साल से रुकी 36 करोड़ 23 लाख की सेलरी नहीं जारी हो पायी है।

जिन टीचरों की तनख्वाह पेंडिंग है उनके बारे में बताते हुए बोर्ड रजिस्टर भावुक होकर बताते हैं कि कि उनके परिवार की हालत बयां करना मुश्किल है।

उनका गुज़ारा कैसे हो रहा है ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर भी ये मदरसा टीचर्स अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले नेताओं और सरकार को सोचना चाहिए कि जिन मदरसा पॉलिटिक्स पर वो अपनी सियासी रोटियां पकाते हैं उन मास्टरों के घरों में रोटियां कैसे पक रही होंगी ? उत्तराखंड की माजूदा भाजपा की धामी सरकार, अल्पसंख्यक मंत्री चन्दन राम दास और अल्पसंख्यकों के नेता बंनने की कोशिश कर रहे वक़्फ़ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स जैसे लीडरों को संजीदगी से ऐसे मसलों को हल करना चाहिए जिससे शिक्षा और विद्यार्थी के बीच शिल्पकार की भूमिका निभा रहे इन मदरसा टीचरों की आँखे नाउम्मीदी और बेबसी में नम न हों।

भारतीय सेना में तैयार होगी लेडी कमांडो की फौज!

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट, 12 दिसंबर, भारतीय नौसेना ने महिलाओं के लिए खोले विशेष बल भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार महिलाओं को कमांडो (Women Commando) के तौर पर काम करने का मौका मिलेगा. जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। भारतीय नौसेना ने अपने एलीट स्पेशल फोर्सेज में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पहली बार महिलाओं को सेना में कमांडो के रूप में सेवा देने की अनुमति दी गई है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने मिडिया को यह जानकारी दी। इस बीच, अभी तक इस फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस संबंध में जल्द ही एक ऐतिहासिक घोषणा होने की संभावना है।

सेना में पहली बार महिलाओं को कमांडो बनने का मौका मिला है

थल सेना, नौसेना और वायु सेना के विशेष बलों में कमांडो को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कमांड विशेष और गुप्त ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्पेशल फोर्स के कमांडो इस काम में दक्ष होते हैं। अभी तक इस कमांडो के लिए केवल पुरुषों को ही अनुमति दी जाती थी। लेकिन अब भारतीय नौसेना महिलाओं को भी कमांडो बनने का मौका देने जा रही है।

महिलाओं के लिए मार्कोस बनने का मौका

सूत्रों के मुताबिक अब अगर महिलाएं ट्रेनिंग के बाद मापदंड पूरा करती हैं तो उन्हें नौसेना में मरीन कमांडो यानी मार्कोस बनने का मौका मिलेगा. भारत के सैन्य इतिहास में यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन किसी को भी सीधे स्पेशल फोर्सेज में शामिल नहीं किया जाएगा। महिला कमांडो को वॉलंटियर के तौर पर काम करना होगा। एक अधिकारी के हवाले से सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाली अग्निवीर भर्ती में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों और नाविकों को मार्कोस प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी.

मार्कोस क्या है? (MARCOS क्या है) – मरीन कमांडो)

MARCOS, समुद्री कमांडो के लिए खड़ा है। समुद्री कमांडो भारतीय नौसेना के विशेष बल कमांडो हैं। नेवी में मार्कोस को कई स्पेशल मिशन के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। ये कमांडो समुद्र, हवा और जमीन में खास मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ये कमांडो दुश्मन के युद्धपोतों, सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं और विशेष डाइविंग ऑपरेशन जैसे गुप्त मिशन को अंजाम देते हैं। MARCOS समुद्री क्षेत्र में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है और उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। फिलहाल कुछ मार्कोस कश्मीर के वुलर झील इलाके में आतंकवाद विरोधी भूमिका में तैनात हैं.

पौड़ी पुलिस का किरायेदारों/ मजदूरों का सत्यापन अभियान तेज़

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पौड़ी , 12 दिसंबर , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , जनपद पौड़ी गढ़वाल, श्वेता चौबे द्वारा बाहरी राज्यों, जनपद पौड़ी में आने वाले, निवासरत एवं कार्यरत व्यक्तियों का जनहित में सत्यापन हेतु पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों को साप्ताहिक दिवस रविवार को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में छात्रों, श्रमिकों, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर अग्रिम सत्यापन की कार्यवाही हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में जनपद के थाना प्रभारियों ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम गठित कर वृहद स्तर पर डोर टू डोर सत्यापन अभियान चलाकर 136 किरायेदार, 67 मजदूर, 81 रेड़ी/ठेली वालों के सत्यापन की कार्यवाही की ।सत्यापन न करने वाले 13 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-83 के तहत रु0 1,30,000/- (श्रीनगर-2, कोटद्वार-05, लक्ष्मणझूला- 03, पौड़ी-01, थलीसैण-01, महिला थाना श्रीनगर-01) के चालान न्यायालय को प्रेषित किये गये।

उत्तराखंड और इसके हसीन चेहरे....

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

गर्मी हो या सर्दी, उत्तराखंड की आबोहवा ऐसी रहती है कि इसे महसूस करने के लिए शहर और दुनिया के कोने-कोने से लोग आते हैं। ऐसे में इस ठंड के मौसम में उत्तराखंड में पर्यटकों की काफी भीड़ देखी जा रही है। उत्तराखंड हमेशा अपने पहाड़ों और घाटियों के लिए यात्रियों को आकर्षित करता है और इस समय उत्तराखंड का तापमान धीरे-धीरे ठंड की चादर में लिपटने जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि आने वाले समय में यहां का माहौल किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं होगा।उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है, लेकिन घबराएं नहीं, यह बर्फबारी जल्द रुकने वाली नहीं है। अतः उत्तराखंड आप सभी देशी-विदेशी पर्यटकों का, जो हिमपात का आनंद लेना चाहते हैं, हार्दिक स्वागत करता है। लेकिन ध्यान रहे कि उत्तराखंड को एक शांत और सुंदर शहर बनाने में आपका भी उतना ही सहयोग चाहिए, जितना उत्तराखंड के निवासी दे रहे हैं, जैसेः

1. ट्रैफिक का पालन करें, ओवरलोडिंग से बचें
2. स्वच्छ भारत अभियान का ध्यान जरूर रखें
3. बर्फबारी के चलते स्लिपरी टैरो के लिए चेन जैसी चीजें लें
4. टूर प्लान करने से पहले अपने या साथ में आने वाले वाहनों को फिट करवा लें
5. अपने साथ अच्छी यादें लेकर जाएं, शराब पीकर गाड़ी न चलाएं

यदि आप उन लोगों में से हैं जो सर्दियों की हवाओं और पहाड़ों में बर्फ का सामना करना पसंद करते हैं तो अपने कार्यालय में छुट्टी के लिए आवेदन करें, अपने परिवार या दोस्तों के साथ सर्दियों की जैकेट खरीदें और आकर बर्फबारी का आनंद लें।

एनडीपीएस व गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की अवैध सम्पत्ति करें सीज़ : डीआईजी गढ़वाल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 12 दिसंबर। डीआईजी गढ़वाल करन सिंह नगन्याल ने पुलिस लाइन देहरादून में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों की गोष्ठी ली। गोष्ठी के दौरान उन्होंने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये :

- अपराध होने से पहले ही उसे रोकने पर काम करें, साथ ही आदतन अपराधियों की कुंडली खंगालते हुए उनके खिलाफ गुण्डा, गैंगस्टर की कार्यवाही में तेजी लाएं। विगत एक दो वर्षो की लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण शीघ्र करें। शिकायतकर्ताओं की शिकायत का निस्तारण का समयबद्ध तरीके से करें, जिससे उनकी समस्या का समाधान समय से हो सके। यदि हम शिकायत या विवेचना का निस्तारण समय से करेंगे तो सही मायने में तभी उन्हें न्याय मिल सकेगा। अपराधियों में पुलिस का भय होना बहुत जरूरी है। गोष्ठी के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि

पुलिस मुख्यालय व उनके कार्यालय स्तर से वांछित व मफरूर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियानों को प्रार्थमिकता के आधार पर सफल बनाएं। अपने अधिनस्थों को मोटिवेट करें और उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारी देते हुए सभी लोग आपस में समन्वय स्थापित कर अच्छी पुलिसिंग पर फोकस करें। जनपद में जितने भी एसआर केस लम्बित चल रहे हैं, उन्हें सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी प्रत्येक सप्ताह पर्यवेक्षण कर विवेचकों का उचित मार्गदर्शन कर उनका निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। अपराधियों को सजा दिलवाना पुलिस का काम है, पुलिस को भयमुक्त समाज बनाना है। जनपद में जितने भी ईनामी और वांछित बदमाश है उन पर थाना क्षेत्रों में अलग-अलग पुलिस टीम गठित कर शत-प्रतिशत कार्यवाही अमल में लाई जाये। एनडीपीएस एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में अभियुक्त द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ति को सीज करने की कार्यवाही की जाये। जिन वांछित अपराधियों में ईनाम घोषित नहीं किया गया है, ईनाम घोषित करते हुए पूर्व घोषित किये गये ईनामों की धनराशि बढाई जाये। 07 साल से कम सजा के अपराधों में जिन अभियुक्तगणों को धारा 41-क का नोटिस दिया जा रहा है, उसका एक अध्यावधिक रजिस्टर थाने में बनाया जाये। गम्भीर प्रकृति के अपराध घटित होने पर पूर्व में प्रकाश में आये अपराधियों के डोजियर को भी घटना स्थल पर ले जाया जाये तथा पीडित व गवाहों को डोजियर दिखाकर अभियुक्तों की तजदीक किया जाये। सी0एम0 हैल्पलाइन के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण देय समयावधि में कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक शिकायत पर घटनास्थल पर जाकर घटना की जानकारी जरूर करें। किसी भी अभियोग में विवेचना में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाये, जिससे अभियुक्त को किसी भी प्रकार का गिरफ्तारी में लाभ मिल सके। गुमशुदगी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल गुमशुदगी पंजीकृत की जाये, देह समय में गुमशुदगी को अभियोग में तरमीम कर विवेचना बहाल की जाये। नाबालिग गुमशुदगी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाये। नशे के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जाये। मां0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर दी गयी रूलिंग के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त समस्त राजपत्रित अधिकारीगणों व थाना प्रभारियों से उनकी समस्या व विवेचना एवं शिकायतों के विषय में जानकारी प्राप्त की गयी तथा उनका समाधान किया गया। गोष्ठी के दौरान दलिप सिंह कुंवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक देहात, पुलिस अधीक्षक अपराध, जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी तथा सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मौजूद रहे।

डीएम सोनिका ने जनसुनवाई में निपटाए 107 शिकायते, निस्तारण का दिया निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 दिसंबर। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में 107 शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में राजस्व, नगर निगम, एमडीडीए, सिंचाई, विद्युत, समाज कल्याण, लोनिवि, पीएमजीएसवाई आदि विभागों से संबंधित प्राप्त हुई। जिनमें अधिकतर शिकायतें भूमि कब्जा, अतिक्रमण, अवैध निर्माण से संबंधित प्राप्त हुई इसके अलावा आर्थिक सहायता, चकबंदी, वाहन के बीजकों को शस्त्र लाईसेंस, विद्युत कनेक्शन, विधवा पेंशन, साइबर ठगी आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में उनसे संबंधित जो शिकायतें प्राप्त हो रही है उनका त्वरित निस्तारण के साथ ही अपने स्तर पर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करें तथा जिन शिकायतों में मौका मुआवना कर निस्तारण किया जाना है विभागीय टीमें भेजकर मौका मुआवना कराएं। तथा टीम रिर्पोट के पश्चात स्वयं भी निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए शिकायतों का निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने विकासनगर क्षेत्र में भूमि पर कब्जा, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर उपजिलाधिकारी विकासनगर को मौका मुआवना करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार तहसील सदर अन्तर्गत भूमि संबंधी प्रकरणों पर उप जिलाधिकारी सदर को निरीक्षण करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए तथा अवैध निर्माण के प्रकरणो पर एमडीडीए के अधिकारियों को जांच करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के साथ ही समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 एस.के बरनवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, अपर मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम जगदीश लाल, प्रशिक्षू आईएएस वरूणा, उप जिलाधिकारी सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण आरसी तिवारी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 मनोज कुमार उप्रेती, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ0 विद्याधर कापड़ी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास अखिलेश मिश्रा, एमडीडीए से अभियन्ता अजय माथुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून में अवैध रूप से पार्किंग करने पर वाहन मालिक उठाएंगे टोइंग चार्ज

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

शहर के वाहन मालिकों को अब देहरादून में अवैध रूप से सड़क किनारे या 'नो पार्किंग' क्षेत्रों में वाहन पार्क करने पर टोइंग चार्ज देना होगा. ट्रैफिक पुलिस विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 127 में प्रावधान है कि वाहन मालिक को अवैध पार्किंग शुल्क के साथ टोइंग शुल्क भी वहन करना होगा।पुलिस अधीक्षक (एसपी), यातायात, अक्षय कोंडे ने कहा - ₹हम अब तक केवल पार्किंग शुल्क (लगभग 500 रुपये) चार्ज कर रहे थे, लेकिन अब हमें सरकार से मंजूरी मिल गई है और पीपीपी मोड में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10 क्रेन शहर में अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटाने के लिए काम करेंगे। सड़क के किनारे। टोइंग शुल्क वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा, जिसके कारण पार्किंग शुल्क अब बढ़ जाएगा₹ ।अधिकारियों को नए साल में नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। एसपी ने कहा कि वर्तमान में उनके पास विभाग के पास केवल तीन क्रेन हैं और बहुत सीमित जनशक्ति है जिसके कारण नियमों का कार्यान्वयन और वाहनों की टोइंग नियमित रूप से नहीं हो पा रही है.

नई व्यवस्था से अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। घंटाघर से राजपुर रोड या घंटाघर से चकराता रोड और सहस्त्रधारा रोड से रायपुर तक के मार्ग जैसे शहर के नौ जोन नो पार्किंग क्षेत्र बन जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि इन मार्गों पर टोइंग क्रेन लगातार खड़ी की जाएंगी और लोग अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। इस साल अक्टूबर तक शहर में 11,377 वाहनों को टो किया गया।एसपी ने यह भी कहा कि वे शहर में और अधिक पार्किंग स्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जिला प्रशासन को पहले ही लिख चुके हैं। अधिक पार्किंग स्थल विकसित करने पर काम चल रहा है और स्थानीय जनता द्वारा भी अनुरोध किया गया है।₹यातायात और पार्किंग की जगह शहर में एक दुःस्वप्न है और समस्या वर्षों में हल नहीं हुई है। गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों को दंडित करना ठीक है, लेकिन जब शहर में कहीं भी पार्किंग उपलब्ध नहीं है तो लोग क्या करते हैं? हमें एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है।₹ इस समस्या के लिए,₹राजेंद्र नगर निवासी डीडी अरोड़ा ने कहा।इस बीच, स्थानीय लोग और अधिकारी इस बात से सहमत हैं कि पार्किंग की समस्या के प्रति लोगों को भी संवेदनशील बनाने की जरूरत है। राजपुर रोड, क्लॉक टावर, बल्लूपुर और अन्य क्षेत्रों के साथ कई परिसरों में, सतह और बेसमेंट पार्किंग उपलब्ध हैं, लेकिन लोग पार्किंग शुल्क बचाने के लिए सड़क के किनारे पार्क करना पसंद करते हैं।एक अधिकारी ने कहा, ₹लंबे समय तक समस्या को हल करने से पहले सार्वजनिक मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है।₹

क्या आप जानते हैं Fixed Deposits करने के बड़े फायदे ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 12 दिसंबर , हर किसी की इच्छा होती है कि उसके बचत पर सबसे ज्यादा ब्याज तो मिले ही साथ ही उसकी सुरक्षा की गारंटी भी. अमूमन बाजार से जुड़े प्रचलित प्लान में समस्या बाजार के उतार-चढ़ाव के साथ पैसे का कम ज्यादा होना दिक्कत सा लगता है. ऐसा ही नहीं है यदि जरूरत पर आपको पैसा निकालना है तब उस समय बाजार की चाल कैसी है इस आपके जमा धन की वापस की रकम तय होती है. यही कारण है कई लोग बाजार से जुड़ी तमाम योजनाओं से दूरी बनाए रखते हैं. आखिर ऐसे लोग market link plan के बजाय सुरक्षित योजना में क्यों निवेश करते हैं. हम आपको 5 आसान कारण बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको भी निवेश करते समय ध्यान में जरूर रखना चाहिए.

फिक्स्ड डिपॉजिट करते समय बैंक में जो ब्याज दर होती है और जो रकम मैच्योरिटी पर दी जानी है वह उस समय दी जाती है. साथ ही बाजार के उतार चढ़ाव पर ब्याज दर पर असर नहीं पड़ेगा. बैंक यदि ब्याज दर बदलता भी है, तब भी मैच्योरिटी की रकम नहीं बदलती. यह निवेश निश्चित कालावधि के लिए होता है. अकसर देखा जाता है कि बैंकों के बचत खाते में रखी रकम से ज्यादा ब्याज एफडी पर मिलता है.

जमा राशि और मैच्योरिटी रकम वापसी की गारंटी

किसी भी बैंक में किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम की गारंटी होती है. यह शेड्यूल बैंक किए गए एफडी की डीआईसीजीसी DICGC (निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम Deposit insurance and Credit guarantee corporation) गारंटी देता है. डीआईसीजीसी RBI (आरबीआई) द्वारा संचालित संस्था है. DICGC द्वारा FD, RD और चालू खाता के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. यह कवर हर बैंक में हर निवेशक के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक होता है. यह भी तब संभव है जब बैंक दिवालिया हो जाए. वरना बैंक तय तिथि पर तय रकम जमाकर्ता को दे देगा.

टैक्स में छूट

बैंकों से मिली एफडी की रकम पर टैक्स में छूट ली जा सकती है यदि इसे कम से कम 5 साल के लिए रखा जाए. एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं. हालांकि मिले ब्याज पर जमाकर्ता को नियमानुसार टैक्स देना होता है.

एफडी पर मिलता है लोन

एफडी पर लोन की सुविधा भी मिलती है. एफडी पर मिलने वाला लोने एक प्रकार से ओवरड्राफ्ट सुविधा होती है. अकसर बैंक एफडी पर देने वाले ब्याज से 2 प्रतिशत अधिक ब्याद पर लोन दे दिया करते हैं. साथ ही एफडी की रकम पर ही लोन दी जाने वाली रकम की सीमा तय होती है. खास बात यह है कि लोन की अवधि के दौरान भी जमाकर्ता को एफडी का ब्याज यथावत जोड़ा जाता है.

एफडी के एवज में क्रेडिट कार्ड

जिन लोगों को क्रेडिट स्कोर कम होता है उन लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलने में काफी दिक्कतें आती हैं. लेकिन ऐसे लोग अपनी एफडी के एवज में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं. कुछ वित्तीय संबंधी कंपनियां इस प्रकार की सुविधी देती हैं.

क्या आपको पता है प्याज काटते समय चिंगम चबाने से आंखों में आंसू नहीं आते हैं

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

खेती की गई प्याज, एलियम सेपा, दुनिया भर के व्यंजनों का एक स्वादिष्ट प्रधान है। फिर भी प्याज़ को काटने से अक्सर आँसू निकल आते हैंः आप पपड़ी की बाहरी त्वचा को छीलते हैं, काटना शुरू करते हैं और जल्द ही, आपकी आँखों में इतना पानी आ रहा है कि आप मुश्किल से देख सकते हैं; आपकी नाक पागलों की तरह दौड़ती है और आपको आश्चर्य होता है कि किसी को इस पीड़ा को रोकने का एक अच्छा तरीका क्यों नहीं मिला।

सुझाए गए समाधान लाजमी हैंः

चिंगम चबाने,पानी के नीचे प्याज छीलें,एक तेज चाकू का प्रयोग करें,सुनिश्चित करें कि प्याज ठंडे हैं,पास में एक मोमबत्ती जलाओ,एग्जॉस्ट फैन चालू करो,

काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए गॉगल्स पहनें, या अच्छे शेफ की तकनीक का इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा, इसे करने के लिए किसी और को प्राप्त करें।जब हम प्याज काटते हैं, तो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं एंजाइम

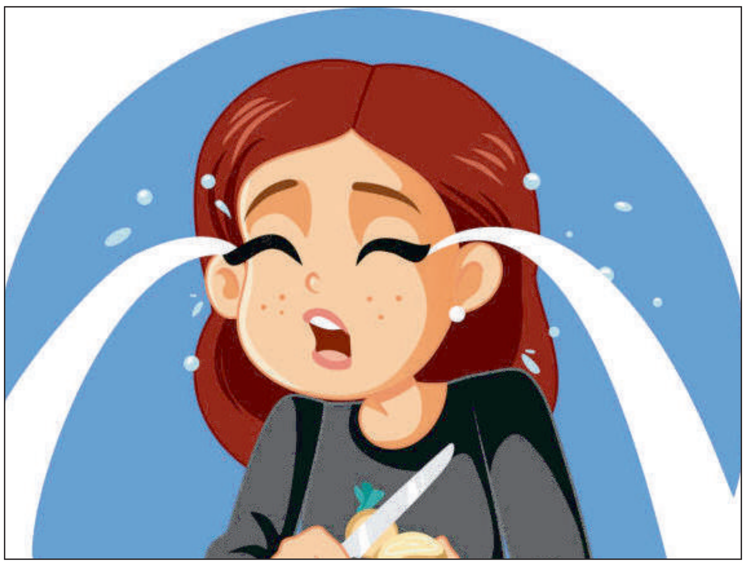

छोड़ती हैं जो सल्फेनिक एसिड के व्युत्पन्न के रूप में टूट जाती हैं। यह तेजी से एक और एंजाइम, लैक्रिमेट्री फैक्टर सिंथेज़ द्वारा

वाष्पशील गैस (प्याज लैक्रिमेटरी फैक्टर) में परिवर्तित हो जाता है। लैक्रिमेटरी कारक सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड सहित हानिकारक यौगिकों की एक श्रृंखला का उत्पादन करने के लिए कॉर्नियल सतह पर पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है।

च्यूइंग गम कैसे मदद कर सकता है?

जब हम च्युइंग गम चबाते हैं तो हम मुंह से सांस लेते हैं। उत्तेजक पदार्थ घुल जाता है। गैस रसायन की थोड़ी मात्रा ही हमारी आंखों की लैक्रिमल ग्रंथियों तक पहुंचती है। इस तरह, ग्रंथियां आंसू नहीं बना सकती हैं और हम रोते नहीं हैं। अगली बार, जब आप रसोई में अपनी माँ की मदद करें या प्याज काटने का अधिकार लें, तो अपने आप को गोंद से पुरस्कृत करें।

देहरादून में अवैध रूप से पार्किंग करने पर वाहन मालिक उठाएंगे टोइंग चार्ज

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

शहर के वाहन मालिकों को अब देहरादून में अवैध रूप से सड़क किनारे या 'नो पार्किंग' क्षेत्रों में वाहन पार्क करने पर टोइंग चार्ज देना होगा. ट्रैफिक पुलिस विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 127 में प्रावधान है कि वाहन मालिक को अवैध पार्किंग शुल्क के साथ टोइंग शुल्क भी वहन करना होगा।पुलिस अधीक्षक (एसपी), यातायात, अक्षय कोंडे ने कहा - ₹हम अब तक केवल पार्किंग शुल्क (लगभग 500 रुपये) चार्ज कर रहे थे, लेकिन अब हमें सरकार से मंजूरी मिल गई है और पीपीपी मोड में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10 क्रेन शहर में अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटाने के लिए काम करेंगे। सड़क के किनारे। टोइंग शुल्क वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा, जिसके कारण पार्किंग शुल्क अब बढ़ जाएगा₹।अधिकारियों को नए साल में नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। एसपी ने कहा कि वर्तमान में उनके पास विभाग के पास केवल तीन क्रेन हैं और बहुत सीमित जनशक्ति है जिसके कारण नियमों का कार्यान्वयन और वाहनों की टोइंग नियमित रूप से नहीं हो पा रही है.नई व्यवस्था से अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। घंटाघर से राजपुर रोड या घंटाघर से चकराता रोड और सहस्त्रधारा रोड से रायपुर तक के मार्ग जैसे शहर के नौ जोन नो पार्किंग क्षेत्र बन जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि इन मार्गों पर टोइंग क्रेन लगातार खड़ी की जाएंगी और लोग अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। इस साल अक्टूबर तक शहर में 11,377 वाहनों को टो किया गया।एसपी ने यह भी कहा कि वे शहर में और अधिक पार्किंग स्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जिला प्रशासन को पहले ही लिख चुके हैं। अधिक पार्किंग स्थल विकसित करने पर काम चल रहा है और स्थानीय जनता द्वारा भी अनुरोध किया गया है।₹यातायात और पार्किंग की जगह शहर में एक दुःस्वप्न है और समस्या वर्षों में हल नहीं हुई है।

गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों को दंडित करना ठीक है, लेकिन जब शहर में कहीं भी पार्किंग उपलब्ध नहीं है तो लोग क्या करते हैं? हमें एक स्थायी समाधान की आवश्यकता है।₹ इस समस्या के लिए,₹राजेंद्र नगर निवासी डीडी अरोड़ा ने कहा।इस बीच, स्थानीय लोग और अधिकारी इस बात से सहमत हैं कि पार्किंग की समस्या के प्रति लोगों को भी संवेदनशील बनाने की जरूरत है। राजपुर रोड, क्लॉक टावर, बल्लूपुर और अन्य क्षेत्रों के साथ कई परिसरों में, सतह और बेसमेंट पार्किंग उपलब्ध हैं, लेकिन लोग पार्किंग शुल्क बचाने के लिए सड़क के किनारे पार्क करना पसंद करते हैं।एक अधिकारी ने कहा, ₹लंबे समय तक समस्या को हल करने से पहले सार्वजनिक मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है।

क्या उबला हुआ आरओ का पानी पिया जा सकता है ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आरओ का पानी उबालना सुरक्षित है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे और रिवर्स ऑस्मोसिस करने के बाद उबालने पर पानी से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा, आरओ पानी में 90% से 95% जहरीले प्रदूषकों को हटा सकता है, जबकि पानी को उबालने से कुछ बचे हुए को खत्म करने में मदद मिलेगी।हां, आप उबला हुआ आरओ का पानी पी सकते हैं लेकिन उबालने की प्रक्रिया में समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है क्योंकि आरओ प्रक्रिया में लवण और बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरओ का पानी (उबला हुआ या नहीं) पीना इंसानों और जानवरों के लिए आदर्श है या नहीं है?NIH के अनुसार, आरओ प्यूरीफायर पानी से मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे कुछ लाभकारी पोषक तत्वों को हटा देते हैं, जिससे इसे लंबे समय तक पकाने और पीने के लिए असुरक्षित बना दिया जाता है।जैसा कि आप आगे पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ का उपयोग करने के क्या फायदे हैं और आरओ-प्यूरीफाइड पानी को उबालकर क्या किया जा सकता है। साथ ही, आपको आरओ के पानी के लंबे समय तक सेवन के साथ-साथ कुछ आरओ विकल्पों के कुछ दुष्प्रभाव भी दिखाई देंगे।

क्या आरओ से फिल्टर करने के बाद पानी उबालना चाहिए?

आरओ से फिल्टर किया हुआ पानी उबालना जरूरी नहीं है। आरओ तकनीक 'टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड' (टीडीएस) को कम करती है और बैक्टीरिया को हटाती है; बैक्टीरिया और वायरस आरओ सिस्टम से नहीं बह सकते। पूरा लाभ लेने के लिए आरओ सिस्टम को पंचर न करें। कुछ पानी आरओ झिल्ली के बिना इसे अलग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।साथ ही, हर तीन महीने में एक बार आरओ पानी की बैक्टीरियोलॉजिकल जांच करना बेहतर होता है ताकि मल संदूषण की तलाश की जा सके और उपकरण और पानी को साफ रखने के लिए उन्हें हटा दिया जा सके। यदि एस्चेरिचिया कोलाई जैसे बैक्टीरिया उच्च सांद्रता वाले पानी में पाए जाते हैं, तो आरओ झिल्ली को जल्दी से बदल दें।

क्या आरओ का पानी उबालने से यह पीने के लिए असुरक्षित हो जाता है?

पानी को उबालने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और उसमें मौजूद लवण निष्क्रिय हो जाते हैं। आरओ से गुजरने वाले पानी को दोबारा उबालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूवी/ओजोन क्लीनर और आरओ दोनों एक ही काम करते हैं, हालांकि सीसे जैसे अन्य दूषित पदार्थों को फिल्टर करना मुश्किल होता है। हालांकि, इसे छानने के लिए पानी उबालना सुरक्षित है।याद रखें कि आरओ फिल्ट्रेशन से गुजरने वाले पानी का पीएच मान कम होता है। पानी में जैविक सूक्ष्म जीव और अवांछित रोगाणु सभी उबालने से नष्ट हो जाते हैं। यदि आप किसी अन्य जल स्रोत तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो रोगजनकों को हटाने के लिए पानी को उबाल लें और इसे पीने के लिए उपयुक्त बना लें।

संपादकीय

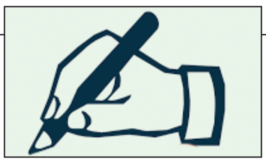

असाध्य रोगों से जूझते बुजुर्ग

असाध्य बीमारियों से जूझते बुजुर्गों की सुध लेने वाला कोई नहीं है. न सरकार को उनकी चिंता है और न उनकी औलादें ही उनकी देखभाल को तैयार हैं. उस देश में, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर आधे से ज्यादा केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नागरिक हों, उस देश के तीन में से दो बुजुर्ग नागरिक असाध्य रोगों से जूझ रहे हों, यह चिंताजनक है. यह आंकड़ा सरकार ने दो साल पहले जारी किया था, लेकिन इस संबंध में किसी प्रकार की कोई योजना लागू नहीं की गयी है. ऐसे पौने आठ करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों का यह आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है. तीन प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ने वाली यह संख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही, तो 2050 में यह संख्या 31.9 करोड़ तक हो जायेगी. खतरे की बात यह है कि इतना सब कुछ जानने-सुनने के बावजूद सरकार कोई ठोस पहल नहीं कर रही है. 45 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुषों और स्त्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को केंद्र में रख कर किया गया यह अध्ययन विश्व का सबसे बड़ा अध्ययन है. यह भारत में पहली बार हुआ है. रोगियों की यह दर शहरों में अधिक है. दुख की बात यह है कि इनमें 78 फीसदी से अधिक के लिए पेंशन की कोई सुविधा नहीं है. भारत के बुजुर्गों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक रोगी हैं. वृद्धावस्था के रोग सबके लिए कष्टप्रद होते हैं, लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले देश के नागरिकों के लिए ये बेहद कष्टप्रद साबित होते हैं. भारत इसी श्रेणी में है. संयुक्त राष्ट्र देशों को वृद्धजनों के लिए नीतियां बनाने और कार्यक्रम चलाने के लिए उत्साहित करता रहा है. संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1991 में वृद्धजनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की नीति अपनायी गयी, 1992 में महासभा द्वारा एक घोषणा पत्र जारी हुई तथा वृद्धावस्था पर वैश्विक लक्ष्य जैसे कार्यक्रम बनाये गये. राष्ट्रीय नीति वृद्धजनों को आश्वासन देती है कि उनकी चिंताएं राष्ट्र की समस्या है. उन्हें न तो असुरक्षित जिंदगी बितानी होगी और न ही वे हाशिये पर या तिरस्कृत रहेंगे. राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य वृद्धजनों का कल्याण है. इसका उद्देश्य है समाज में इन लोगों की वैध स्थिति मजबूत बनाना और इनकी जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण, सम्मानजनक एवं शांतिपूर्ण बनाना. हमारे देश की राष्ट्रीय वृद्धजन नीति मानती है कि बुजुर्गों के हित में एक निश्चित कार्यक्रम की आवश्यकता है. हमें सुनिश्चित करना है कि बुजुर्गों के अधिकारों का हनन नहीं हो तथा उन्हें उचित अवसर एवं बराबरी मिले. हमारे संविधान में वृद्ध व्यक्तियों की भलाई को अनिवार्य किया गया है. अनुच्छेद 41 (राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत) ने निर्देश दिया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर वृद्धावस्था के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा. वृद्धों की उपेक्षा केवल सरकार द्वारा ही नहीं की जाती है, बल्कि उस परिवार, जहां वे रहते हैं, में भी वे प्रायः उपेक्षा के शिकार होते पाये जाते हैं. 'बुढ़ापे की लाठी' मुहावरा तो प्राचीन काल में गढ़ा गया था. वर्तमान में आते-आते देखा गया है कि प्रायः यही संतान अपने वृद्ध माता-पिता पर ही लाठी भांजने लग जाती है. ज्यादातर मामलों में जिन संतानों को पाल-पोस कर पल्लवित और शिक्षित करने में उन माता-पिता ने अपना सर्वस्व दिया होता है, उम्र के शीर्ष पर पहुंच कर वे उन्हीं पुत्र-पुत्रियों से हिकारत प्राप्त करने लग जाते हैं. विभिन्न सर्वे में प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि रोगी माता-पिता की उपेक्षा में बेटे ज्यादा अग्रणी रहते हैं, बेटियों का ग्राफ इस मामले में अधिक बेहतर है. जहां माता-पिता वित्तीय रूप से निर्बल या अक्षम होते हैं, उपेक्षा का यह प्रतिशत वहां और ज्यादा बड़ा हो जाता है. इस दिशा में वैसे तो संसद ने वृद्धजन कानून 'माता- पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007' के नाम से पारित किया है और सरकार ने इसे लागू कर रखा है, लेकिन दूसरे कानूनों की भांति इसका भी विधिवत पालन नहीं हो पाता है.

रोटरी क्लब दून शिवालिक हिल्स एवम जगतबंधु सेवा ट्रस्ट के सौजन्य निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन

मो.सलीम सैफी
न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून,12 दिसंबर।रोटरी क्लब दून शिवालिक हिल्स एवम जगतबंधु सेवा ट्रस्ट के सौजन्य निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन सीमा द्वार शास्त्री नगर शिव शक्ति मंदिर में आयोजित किया गया जिसमें 150 से अधिक क्षेत्र वासियों के द्वारा निशुल्क आंखों की जांच कराई गई। रोटरी क्लब दून शिवालिक हिल्स अध्यक्ष तपन कौशिक जी के द्वारा बताया गया कि रोटरी क्लब दून शिवालिक हिल्स के माध्यम से इस वर्ष उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों से 5000 से अधिक निशुल्क ऑपरेशन कराए जाएंगे। शिविर में मुख्य अतिथि डॉ अजीत तिवारी कैंसर सर्जन गोल्ड मेडलिस्ट जी मौजूद रहे। साथ ही साथ रोटरी क्लब दून शिवालिक हिल्स के द्वारा डॉ अजीत तिवारी को देहरादून रतन सम्मान से सम्मानित किया गया डॉ अजीत तिवारी के द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद कैंसर से पीड़ित मरीजों की निशुल्क सेवा की जा चुकी है। शिविर में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल से आए डॉक्टर शिवानी रतूड़ी और डॉक्टर राजेश्वर के द्वारा सभी क्षेत्रवासियों की निशुल्क जांच कर उन्हें दवाइयां प्रदान की गई। शिविर में 18 मरीजों को ऑपरेशन हेतु चयन किया गया। शिविर में दिवेश गर्ग सचिव, अनिल, जी डी शर्मा, सुमित प्रजापति, अनिल धस्माना जी, सुरेश, मोजूद रहे.

यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल डेट 16 से 28 फरवरी तक, 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च में

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

UP: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी द्वारा राज्य के सम्बद्ध शासकीय और निजी विद्यालयों में वर्ष 2022-23 के दौरान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में पंजीकृत 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं के क्रम में प्रायोगिक परीक्षाएं फरवरी के आखिरी दो सप्ताह के दौरान होंगी। परिषद द्वारा जारी वर्ष 2022-23 के लिए का एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं 16 से 28 फरवरी 2023 के बीच आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

यूपीएमएसपी द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मार्च 2023 के दौरान किया जाएगा। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए विषयवार परीक्षा तारीखों के लिए यूपीएमएसपी टाइम टेबल 2023 फिलहाल जारी नहीं किया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं डेट शीट 2023 को जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट, upmsp.edu.in पर जारी कर सकता है। हाईस्कूल के परीक्षार्थियों को यूपीएमएसपी 10वीं डेट शीट 2023 और इंटर के स्टूडेंट्स को यूपीएमएसपी 12वीं डेट शीट 2023 के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहना चाहिए।

यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के लाखों स्टूडेंट्स के लिए वार्षिक प्रायोगिक व सैद्धांतिक परीक्षाओं से पहले प्री-बोर्ड के आयोजन के लिए तारीखों का निर्धारण किया है। परिषद के कैलेंडर के अनुसार कक्षा 10 और 12 की प्री-बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह से आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद, दोनों कक्षाओं के लिए प्री-बोर्ड लिखित परीक्षाओं का आयोजन 1 से 15 फरवरी तक किया जाएगा। प्री-बोर्ड एग्जाम के बाद यूपीएमएसपी ने इनके मूल्यांकन के लिए 16 से 28 फरवरी तक की अवधि निर्धारित की है

इस ड्रिंक्स को पीने से बाल, त्वचा और मोटापे की समस्या से मिलेगा निजात

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

नारियल पानी एक ऐसा औषधीय पेय पदार्थ है. अगर आप रोज पीते हैं. तो इस के बहुत लाभ होते हैं. यह स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों होता है. गर्मी के मौसम में तो इसे लोग ज्यादा पीना पसंद करते हैं. क्योंकि ये आपको डिटॉक्स अच्छे से करता है. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर को अलग-अलग तरीके से फायदे पहुंचाते हैं. कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, प्रोटीन, सोडियम, फास्फोरस, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन सी और पोटेशियम मौजूद होते हैं. अगर आप नारियल पानी का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन पर शाइन आएगा. साथ ही चेहरे पर दाने और एक्ने से भी बचे रहेंगे. इसके अलावा फाइन लाइन और झुर्रियां भी नहीं दिखेंगी. नारियल पानी पीने से बालों का झड़ना रूसी से भी निजात मिलती है. वहीं. इसको पीने से बाल की लंबाई में भी इजाफा होता है और चमक भी बरकरार रहती है. इसको पीने से बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में इकट्ठा नहीं होता है. और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. इस लिहाज से दिल की सेहत के लिए ये अच्छा साबित होता है.नारियल पानी पीने से आपका वजन भी कंट्रोल रहता है. इससे आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा नहीं होती है. इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण लिवर के लिए अच्छा साबित होता है.गर्भावस्था में तो महिलाओं को नारियल पानी का सेवन जरूर करना चाहिए. इसके पोषक तत्व मां और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है. इसलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी में नारियल पानी पीने की सलाह जरूर देते हैं.

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा

महिलाओं की मददगार होगी महिला हेल्प डेस्क : श्वेता चौबे एसएसपी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने "नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क" का किया उद्घाटन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

कोटद्वार, 12 दिसंबर। कोटद्वार शहर एक घनी आबादी वाला शहर है। थाना कोटद्वार पर पीड़ित महिलायें अपनी शिकायतें लेकर काफी संख्या में थाना परिसर में पूर्व से ही बने महिला हेल्प डेस्क पर आती थी।

पूर्व से बने महिला हेल्प डेस्क में अपेक्षाकृत जगह कम होने के कारण पीड़ित महिलायें पुलिस को अपनी शिकायत बताने में भीड़-भाड़ होने के कारण असहज महसूस करती थी। पीड़ित महिलाओं की इस समस्या के दृष्टिगत घरेलू हिंसा, पारिवारिक मामलों एवं उत्पीड़न जैसी शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता लाने हेतु थाना परिसर में ही महिला हेल्प डेस्क हेतु पृथक से एक कक्ष तैयार किया गया, जिसका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने उद्घाटन किया। एसएसपी चौबे ने "महिला हेल्प डेस्क" में नियुक्त कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये है जिससे डेस्क की उपयोगिता को सार्थक बनाया जा सके। "महिला हेल्प डेस्क" पर अपनी शिकायत लेकर आने वाली पीड़ित महिला को विश्वास में लेकर उनकी शिकायत को गम्भीरता से ध्यानपूर्वक सुनकर शिकायत का तत्काल निस्तारण करेंगी। "महिला हेल्प डेस्क" पर आने वाले प्रत्येक पीड़ित की शिकायत के सम्बन्ध में एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा जिसमें पीड़िता का नाम, पता, सम्पर्क नम्बर, शिकायत का विवरण अंकित किया जायेगा। उक्त रजिस्टर में Feed Back का कॉलम अवश्य बनाया जाये, जिसमें शिकायत के निस्तारण के पश्चात पीड़िता द्वारा अपनी संतुष्टि/असंतुष्टि के सम्बन्ध में टिप्पणी अंकित की जायेगी। "महिला हेल्प डेस्क" में नियुक्त कार्मिकों को उत्तराखण्ड पुलिस एप के गौरा शक्ति का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर पीड़ित महिलाओं को विश्वास में लेकर एप की उपयोगिता के बारे में जानकारी देकर उनका स्वः रजिस्ट्रेशन करने हेतु प्रेरित करेंगे। जिससे अल्प समय में पीड़िता को पुलिस सहायता उपलब्ध हो सके। थाने पर आने वाली पीड़ित महिलाओं की नियमानुसार कॉउन्सलिंग करने के लिए भी एसएसपी श्वेता चौबे ने निर्देशित किया है ।

उत्तराखंड में दिन-रात के तापमान में पांच साल बाद आया भारी अंतर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

12 दिसंबर, उत्तराखंड में जैसे-जैसे दिसंबर बीत रहा है, वैसे-वैसे पारा रात में गोते लगा रहा है। इससे कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के काफी नीचे चल रहा है। इसके उलट प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन में चटख धूप खिल रही है और अधिकतम तापमान सामान्य या उससे अधिक दर्ज रहा है। दिन में चटख धूप और रात में कड़ाके की ठंड खासकर बुजुर्गों व नौनिहालों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में तापमान में सामान्य से अधिक अंतर को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है।

केंद्र ने बुजुर्गों और बच्चों की सेहत को लेकर बेहद सतर्क रहने का सुझाव भी दिया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर दर्ज किया गया। सबसे अधिक 22.1 डिग्री सेल्सियस का अंतर ऊधमसिंह नगर जिले में देखा गया, जोकि पिछले पांच वर्ष में दिसंबर में प्रदेश के किसी हिस्से में दिन-रात के तापमान में सबसे बड़ा बदलाव है। इदेहरादून में भी अजीब ही रहा है. यहां अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया तो न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। इस तरह दिन और रात के तापमान में 20.6 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया। अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम रहा। पर्वतीय क्षेत्र में भी इन दिनों अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। यहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 13.7 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। दिसंबर महीने का प्रथम पखवाड़े में अभी तक पहाड़ से लेकर मैदान तक कहीं भी वर्षा नहीं हुई जिससे मौसम शुष्क रहा। इसी के चलते कोरी ठंड का प्रकोप दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति लंबे समय तक मौसम शुष्क रहने के कारण बनी है। इस बार पिछले करीब दो महीने से प्रदेश में वर्षा नहीं हुई है।

'वीर बाल दिवस' पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट कराएगा निबंध प्रतियोगिता

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 12 दिसंबर। दसवें गुरु श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी के छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह (9 वर्ष) और साहिबजादा फतेह सिंह (6 वर्ष) ने अपनी छोटी सी उम्र में ही 26 दिसम्बर 1705 में सिख पंथ के गरिमामयी गौरव की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर करके भारत के इतिहास में सर्वोच्च बलिदान दिया था। साहिबजादों की वीरता एवं दिए गए । सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में 25 दिसम्बर को ?वीर बाल दिवस? के रूप में मनाये जाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी जो कि एक ऐतिहासिक व सराहनीय कदम है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा उत्तराखंड सरकार एवं शिक्षा विभाग को पत्र के माध्यम से एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाने का प्रस्ताव दिया था जो कि सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। प्रदेश के विद्यालयों में यह निबंध प्रतियोगिता तीन स्तरों पर की जाएगी (1) विकास खण्ड स्तर (2.) जनपद स्तर (3) राज्य स्तर। इन स्तरों से निबंध प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ आने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के विजेता छात्रों को गुरुद्वारा श्री हेमकुन्ट साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। निबंध प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रतियोगिता से संबंधित सभी दिशा-निर्देश राज्य के विद्यालयों व शैक्षणिक संस्थाओं को प्रेषित किए जा रहे है। अन्य प्रदेशों की सरकार एवं शिक्षा विभाग को भी इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए जिससे की संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सके एवं भविष्य की आने वाले पीढ़ी भी इतिहास से जुड़ी रहें।

बीवी से ज्यादा बार अपना मोबाइल देखते हैं लोग, अजब आदत की गजब बीमारी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट, 12 दिसंबर, वॉट्सऐप (WhatsApp) के फैमिली ग्रुप का मैसेज हो या फिर जोमैटो से कोई ऑफर। फोन पर सोशल मीडिया या दूसरे ऐप्स के नोटिफिकेशन्स हर कुछ मिनट में आपका ध्यान भटकाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फोन साइलेंट मोड पर हो या न हो, आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है...

व्यक्ति हर 15 मिनट में फोन देखता है : एक अनुमान के मुताबिक, हम एक दिन में औसतन 85 बार अपना फोन चेक करते हैं। इसका मतलब हर 15 मिनट में एक बार। यानी हर 15 मिनट में हमारा दिमाग काम से हटकर फोन में लग जाता है। ध्यान तो आसानी से भटक जाता है, लेकिन उसे वापस पाना काफी मुश्किल होता है। अगर हम टीवी देख रहे हैं तब तो ठीक है, पर पढ़ाई, काम और परिवार के साथ वक्त बिताने के दौरान ऐसा होना सही नहीं है।

दो तरह से ध्यान भटकता है

साइकोलॉजी की सीनियर लेक्चरर कहती हैं- फोन में बार-बार बजने वाली घंटी दो तरह से हमारा ध्यान भटकाती है। पहले को एक्सोजेनस इंटरप्शन कहते हैं और दूसरे को एंडोजेनस इंटरप्शन। एक्सोजेनस इंटरप्शन तब होता है जब फोन पर कोई नोटिफिकेशन आता है। इससे हम एक्साइटेड हो जाते हैं। यह उत्सुकता और खुशी वैसी ही होती है जैसी लोगों को जुआ

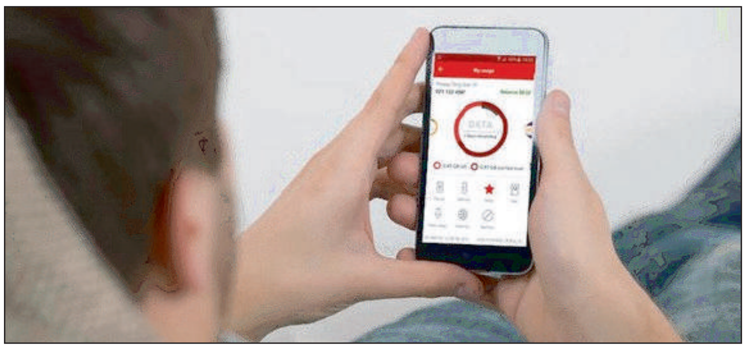

खेलते समय होती है। इससे उन्हें उस चीज की लत लग जाती है। एंडोजेनस इंटरप्शन में आपको अंदर से फोन चेक करने की इच्छा होती है। यानी नोटिफिकेशन न आने पर भी आपका ध्यान काम से हटकर फोन पर जाता है। इससे फिजूल में ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं।

फोन चेक करने से तनाव बढ़ रहा

एक्सपर्ट का कहना है कि बार-बार फोन चेक करने से लोगों में स्ट्रेस बढ़ रहा है। नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया न देने से लोग विचलित हो जाते हैं। उनका ध्यान काम में नहीं लगता। उनमें प्रोडक्टिविटी और फोकस की कमी हो जाती है। एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद काम पर वापस ध्यान नहीं लगता, तो मन में गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन भर जाता है।

बार-बार फोन चेक करने से कैसे बचें?

जिन ऐप्स के नोटिफिकेशन्स काम के नहीं हैं, उन्हें बंद कर दें।रात में फोन को दूसरे कमरे में रखें। इससे आपकी नींद खराब नहीं होगी।फोन चेक करने की इच्छा से लड़ें। खुद से पूछें कि ऐप्स खोलना जरूरी है या नहीं।फोन चलाने को रिवॉर्ड समझें। कम से कम 25 मिनट काम में ध्यान लगाएं और फिर ब्रेक लेकर फोन चेक करें।